अध्याय–6

वैश्वीकरण

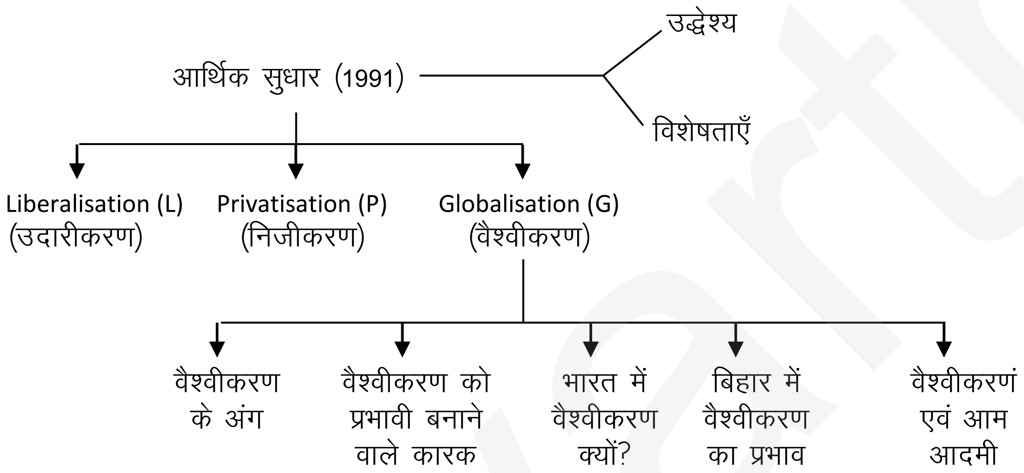

आर्थिक सुधार (1991)

- आर्थिक सुधार का अर्थ है पुरानी नीतियों में परिवर्तन लाकर सामाजिक–आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना।
- सन् 1991 में भारत के वित्तमंत्री के रूप में डॉ0 मनमोहन सिंह के प्रयास से LPG की नीति अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनायी गई, जिससे भारत में अनेक आर्थिक प्रगति हुई।

आर्थिक सुधार नीतियों की मुख्य विशेषताएँ थी :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना
(ii) औद्योगिक नीति को उदार बनाना
(iii) भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना

आर्थिक सुधार के मुख्य उद्धेश्य इस प्रकार थे :

(i) आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना
(ii) आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग
(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार
(iv) उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।

उदारीकरण

- वैसी प्रक्रिया, जिसमें सरकारी नियंत्रण को कम किया जाता है।
- लाइसेंस–परमिट राज समाप्त करके उद्योगपतियों, उद्यमियों तथा उत्पादकों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

https://www.evidyarthi.in/

निजीकरण :

- वैसी प्रक्रिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बदले निजी क्षेत्र को अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्त्व पूर्णतः या अंशतः निजी क्षेत्र को दिया जाता है।

वैश्वीकरण :

- वह प्रक्रिया, जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से जुड़ाव होता है।
- भौगोलिक सीमा समाप्त हो जाती है तथा वस्तुओं के साथ–साथ पूँजी, तकनीक एवं सेवाओं का भी एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी रूकावट के प्रवाह होता है।

वैश्वीकरण के प्रमुख अंग :

- पूँजी की पूर्ण परिवर्त्तनशीलता अर्थात् निर्यात द्वारा प्राप्त अर्जित विदेशी पूँजी को बाजार में बेच सकना।
- पूँजी का स्वतंत्र प्रवाह अर्थात् भारतीय पूँजीपति विदेशों में निवेश कर सकते हैं, तथा विदेशी पूँजीपति भारत में निवेश कर सकते हैं।

तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह

- श्रम का स्वतंत्र प्रवाह
- व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी।

वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक :

- तकनीकी प्रगति में परिवर्त्तन
- उदारवादी नीतियाँ
- प्रतिस्पर्द्धा

भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता

भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जहाँ एक उन्नत बाजार उपलब्ध है। जहाँ उपभोक्ताओं का एक विशाल समूह मौजूद है। भारत में वैश्वीकरण का समर्थन निम्न कारणों से किया जाता है –

(i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु
(ii) अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति हेतु
(iii) उत्पादन के स्तर को उन्नत करने हेतु
(iv) नयी प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक
(v) मानवीय पूँजी की क्षमता का विकास
(vi) प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि
(vii) नये बाजार तक पहुँच

बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव :

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ने किसी एक संदर्भ में कहा था – ''देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है।'' वैश्वीकरण के वर्त्तमान युग में उत्पादन एवं उपभोग

https://www.evidyarthi.in/

के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया है, जिसके सुखद परिणाम बिहार राज्य में भी देखने को मिल रहे हैं। वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। परन्तु सकारात्मक प्रभाव का पलड़ा अधिक भारी है।

बिहार में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि
2. निर्यातों में वृद्धि
3. विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति
4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रगति प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन
5. विश्वस्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता
6. रोजगार के अवसरों में वृद्धि
7. बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन

बिहार में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव

1. कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा
2. कुटीर एवं लघु उद्योग पर विरीत प्रभाव
3. रोजगार पर विपरीत प्रभाव
4. आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश

वैश्वीकरण एवं आम आदमी

आम आदमी से तात्पर्य समाज के वैसे वर्ग–समूह से है जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग होते हैं। जो समाज उपभोग की सुविधाओं से वंचित होते हैं। वैश्वीकरण के पश्चात् जहाँ एक ओर विदेशी पूँजी का ब़ड़ी मात्रा में आयात होने लगा है, वहीं बड़ी–बड़ी कंपनियाँ अपने उद्योग का केन्द्र सस्ते श्रम शक्ति की मौजूदगी के कारण भारत जेसे देश में बनाने लगे हैं। मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का निम्न प्रभाव पड़ा है। :

अच्छा प्रभाव	बुरा प्रभाव
1. रोजगार की बढ़ी संभावना 2. आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता 3. उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता	1. सामान्यतः कम कुशल लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका 2. उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुयी प्रतियोगिता 3. श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव 4. मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई 5. कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट

https://www.evidyarthi.in/

विश्व व्यापार संगठन (W. T. O.) : विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी, जिसका उद्धेश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। W.T.O. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो।

निवेश : अर्थशास्त्र में परिसंपत्तियों, जैसे – भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गयी मुद्रा निवेश कहलाती है।

मॉल : इसमें एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एवं बड़ी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं, उसे मॉल कहते हैं।

व्यापार अवरोधक : सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए करती है।

◆◆◆

https://www.evidyarthi.in/